

मुख्य धारा और समावेशी शिक्षा
 (Mainstreaming and Inclusive education)

सार्वजनिक शिक्षा के इतिहास में शिक्षा के सार्वजनिककरण तथा शैक्षिक व्यवस्था की समावेशी एवं समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवस्थापन के बाद मानव कर्म जा रहे हैं।

इसमें वैश्वीकरण और सरकार द्वारा तथा और सरकारी संस्थानों द्वारा ही Main Stream में जाने का सकारण रूप दिया जा रहा है।

राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तथा अन्य Bodies द्वारा समावेशी शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय युगवासी परिषद् की स्थापना-अधिनियम 1992 के अनुसार की गयी।

व्यक्तियों की शिक्षा को लाने के लिए अधिनियम 1995 पारित किया गया तथा गैर-मौखिक शिक्षा अधिनियम 1999 पारित किया।

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन सभी अधिनियमों तथा वी. जे. एस. की शिक्षा के बारे में विचार किया गया।

वर्तमान संविधान संविधान 93 के संशोधन में भी यह व्यवस्था की गयी कि - 6-14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

→ NCF राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एवं 2000 में समावेशी शिक्षा को विद्यालयों (Inclusive schools) की स्थापना करने का पक्ष दिया। जिसमें कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को

शिक्षा प्रदान करने में सुविधा हो सके।

⇒ वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों के आधार पर ही
कायम, अप्रतिष्ठित एवं विशेष आवश्यकताओं वाले
बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है
जिसे मुख्य धारा में मानने के लिए निम्न आवश्यकता
हैं :-

(1) शिक्षा का सार्वभौमिकरण (Universalisation of Edu.)

(2) सामाजिक न्याय का उद्देश्य (Aims of social jus)

(3) सहयोगी वातावरण का निर्माण (Creation of Co-ope-
-rative Environment)

(4) समग्र विकास का उद्देश्य (Aim of all round
development)

(5) शैक्षिक वातावरण का निर्माण (Creation of educational
environment)

(6) शैक्षिक अवसरों की समानता (Equality of
educational opportunities)

(7) व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य (Aim of individual
development)

(8) सामाजिक समानता का उद्देश्य (Aim of social respect);
समावेशी विद्यालयों में

प्रत्येक क्षेत्र में शाला समानता का प्राप्ति विकसित की जाती है
2017 कायम एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यह शिक्षा प्राप्त
है कि उनका समाज में वही स्थान है जो कि एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए

Impairment, Disability and Handicappedness.
 (बाधित, असमर्थता एवं अपंगाता)

:- विभिन्न बाधकों की शिक्षा प्रदान करने के लिये साधारण शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न शिक्षा की प्रदान करना जति आवश्यक है। विभिन्न शिक्षा में तीन शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। ये शब्द हैं बाधित (Impairment), असमर्थता (Disability) तथा अपंगाता (Handicapped).

- ① बाधित (Impairment)
- ② असमर्थता (Disability)
- ③ अपंगाता (Handicapped)

① बाधित (Impairment) :-

जब कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से काम करने के अयोग्य हो जाता है तो उसे हम बाधित कहते हैं।

परिचय :-

- इसके साधारण मापदण्ड में अन्तर हो जाता है और वह साधारण रूप से कार्य नहीं कर सकता।
- बाधितता जन्म से या जन्म के पश्चात् दुर्घटना, चोट बीमारी या गलत दवा के प्रयोग से हो सकती है।
- बाधितता से उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह शारीरिक रूप से मान्य हो जाता है।
- इसके प्रभाव के कारण उसके लिये उठना-बैठना, चलना-चलना, खाना-पान आदि मुश्किल हो जाता है।

② Disability (असमर्थता) / अक्षमता :-

अक्षमता/असमर्थता की अवधारणा बहुत ही व्यापक है इसके अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्यरत व्यक्ति सम्मिलित होते हैं

इस प्रकार अक्षमता की अवधारणा में मानसिक मर्दा, पियेसियन विकलांगता, बाधित तथा अधिगम अक्षमता का अध्ययन किया जाता है

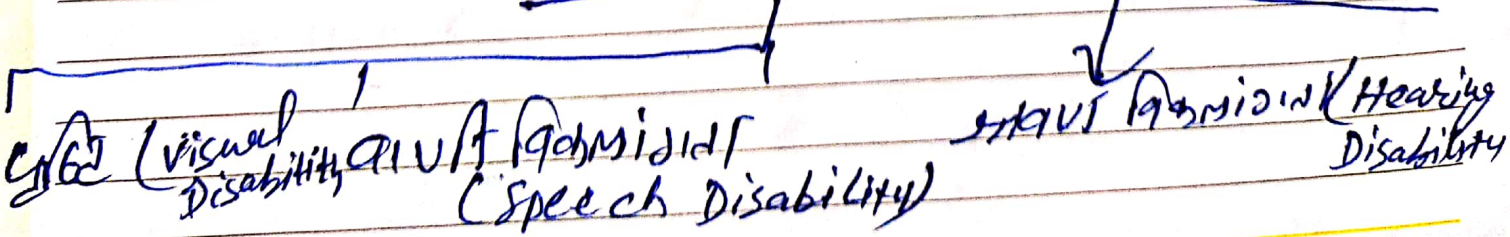
अक्षमता के दो प्रकार के होते हैं :-

- ① शारीरिक अक्षमता (physical Disability)
- ② मानसिक अक्षमता (mental Disability)

① शारीरिक अक्षमता (physical Disability) :-

शारीरिक विकलांगता से अभिप्राय है शरीर के अक्षम होना जैसे - देखने, सुनने, खींचने, चलने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता है

शारीरिक अक्षमता (physical Disability)



3. अपंग (विकलांग)
 (Handicapped) :-

अपंग व्यक्ति को उन समस्याओं से सम्बन्धित है जो बाधा और विकलांग के फलस्वरूप होती हैं।
 अपंग व्यक्ति को उन समस्याओं से सम्बन्धित है जो बाधा और विकलांग के फलस्वरूप होती हैं।
 फूल शब्दों में वह एक लकड़ है - 24 कोष के कारण सही रास्ता ले लीजिए, खेलने तथा पर्याप्त सामाजिक भावनाओं में कठिनाई अनुभव करते हैं विकलांग बच्चे हैं।

Definition of Handicapped :-

B. J. Timari के अनुसार :-

“विकलांग एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति में सामान्य व्यवहार, कार्यशक्ति एवं नियमित कार्यों की व्यापक प्रभावित कर आर्थिक, मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक असुविधा उत्पन्न कर देती है”

SK Sharma

7-III : Policies and Act Implementing Inclusive Education
- शीर्षक : (समावेशी शिक्षा निहितार्थ नीतियाँ और विधियाँ) :-

भारतीय पुनर्वास परिषद् का स्थापना → 1992-2000

भारतीय पुनर्वास परिषद् को सरकार द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि निर्यात व्यक्तियों को जो भी बुद्धिमान ही जाती है उनका क्रिया व्यवहार नियंत्रित करें। यह भारतीय पुनर्वास परिषद् अपने आप में एक सरकारी संस्था है। इसे संसद द्वारा पारित अधिनियम से यह अधिकार प्राप्त है कि निर्यात, वंचित और विशेष आवश्यकता वाले जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम व कौशल बनाये गये हैं उनको नियंत्रित करें।

सरकार द्वारा इसकी स्थापना प्रमुख रूप से इसलिए की गयी है कि जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं के कारण समाज से अलग हो गये हैं अथवा समाज द्वारा उनकी योग्यता को किसी एक क्षमता को होने के कारण नकार दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों को अलग से रोक जाये तथा उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाय।

सामान्य रूप से कौशल भी व्यक्ति जब समाज की धारा से अलग होता है तो उसके अपराध, गरीबी एवं अन्य दुर्भाग्य पर चलने की संभावना होती है।

भारत की पुनर्वास परिषद् के उद्देश्य (Aims of Rehabilitation Council of India) :-

भारत की पुनर्वास परिषद् के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं जो निम्नी ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गयी है :-

1) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, जिससे कि समाज की मुख्य धारा से जुड़े सकें।